under sub-section (3) of section 133 of the Motor Vehicles Act, 1939, read with clause (c) (iv) of the Proclamation dated the 3rd March, 1973, issued by the President in relation to the State of Orissa.

(ii) A statement (Hindi and English versions) explaining the reasons for not laying the Hindi version of the above Notification. [*Placed in Library. See* No. LT-5439/73].

ANNUAL REPORT OF INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MADRAS, 1971-72

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF CULTURE (SHRI D P. YADAV): I beg to lay on the Table a copy of the Annual Report (Hindi version) of the Indian Institute of Technology Madras, for the year 1971-72. [*Placed in Library. See* No LT-5440/73.]

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

SECRETARY: Sir, I have to report the following messages received from the Secretary of Rajya Sabha:—

(i) "In accordance with the provisions of rule 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the Payment of Bonus (Amendment) Bill, 1973, which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 16th August, 1973.".

(ii) "In accordance with the provisions of rule 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the Foreign Awards (Recognition and Enforcement) Amendment Bill, 1973, which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 16th August, 1973."

BILLS AS PASSED BY RAJYA SABHA

SECRETARY: Sir, I lay on the Table of the House the following Bills, as passed by Rajya Sabha:—

(1) The Payment of Bonus (Amendment) Bill, 1973.

(2) The Foreign Awards (Recognition and Enforcement) Amendment, Bill, 1973.

13.10 hrs.

UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (DELEGATION OF POWERS) BILL

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. C. PANT): I beg to move.*

"That the Bill to confer on the President the power of the Legislature of the State of Uttar Pradesh to make laws, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The House is aware that in the proclamation dated 13th June, 1973 in relation to the State of Uttar Pradesh the President has declared the powers of the State Legislature shall be exercised by and under the authority of Parliament.

However, in view of the otherwise busy schedule of the two Houses, it would be difficult for Parliament to deal with the various legislative measures that may be necessary in respect of the State. It would be even more difficult in situations requiring emergent legislation. The Bill, therefore, seeks to confer on the Pre-

*Moved with the recommendation of the President.

[Shri K. C. Pant]

sident the power of the State Legislature to make laws in respect of the State. It has been the normal practice to undertake such legislation in respect of the States under the President's Rule and the present Bill is on the usual lines. Provision has been made for the constitution of a Consultative Committee consisting of Members of Parliament in this regard. Provision is also being made to empower Parliament to undertake modifications in the laws made by the Parliament if considered necessary.

I request the Honourable House to accept the proposal before it.

MR. SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill to confer on the President the power of the Legislature of the State of Uttar Pradesh to make laws, as passed by Rajya Sabha, be taekn into consideration.

Before I allow any discussion, I would like to say that we have had enough of discussions while the U.P. Proclamation was under consideration The Business Advisory Committee, taking full view of this position, has allocated the time schedule of one hour for this discussion. They considered about the time and they put down one hour for this. Previously if was decided to put down both together each having one hour. I would request the Members to confine themselves to this limit.

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, इसका समय बढ़ाना जाये । (व्यवधान) ।

SHRI BISHWANATH ROY (Deoria): This problem has cropped up again and again. And so, more time is needed.

अध्यक्ष महोदय : हमारे पास टाइम इतना कम है कि हमने लंच हावर बन्द कर दिया है और भोजन को भी तीन दिन के लिये बढ़ा दिया है । अब वक्त को खींच कर लम्बा तो नहीं किया जा सकता है ।

I think the Bill is a very small one. Four to Five Minutes for each Member will do.

SHRI S. P. BHATTACHARYYA (Ulluberia): Mr. Speaker, Sir, the Presidential power conferred by Parliament to legislate in Uttar Pradesh is very painful to us. Our Prime Minister, in the course of her election tours, repeatedly said that if the ruling party—Congress—has got a thumping majortiy in very State, then the Government would have stabilised everywhere. Now, what we see here is this. In spite of their having a thumping majority, this Legislature is superseded by the Presidential Rule. We must examine what are the causes behind it. We think that we cannot solve the problems of the people regarding the price rise unemployment, poverty etc. The problems are getting multiplied more and more. In spite of the thumping majority, the Legislature, I should say, is guilty of all these things. You say that because of this you are trying to solve these problems by having a Presidential Rule here. I cannot support this But, Parliament must think over what are the reasons behind this and it should take all real steps so that instability may go and the problem of the State may be really solved by this Parliament of independent India

श्री नरसिंह नारायण पांडे (गोरखपुर) अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति को उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल को विधियां बनाने की शक्ति प्रदान करने के लिये जो बिल लाया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं ।

उत्तर प्रदेश की हालत दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी, जिसको स्वयं मुख्य मंत्री

जी ने गवर्नर को दी गई अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया था । उस रिपोर्ट से प्रकट होता था कि उत्तर प्रदेश में पी० ए० सी० का रिवोल्ट हुआ, स्टुडेंट इनडिसिप्लिन एक खतरनाक सीमा तक पहुच गयी थी और कायदे-कानून की स्थिति बहुत बिगड़ गई थी । इस अवस्था मे बहुमत दल का नेता होने के बावजद मुख्य मंत्री ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा समर्पित किया और केन्द्रीय सरकार को इस बात का मौका दिया कि वहा की शासन व्यवस्था और शासन-तत्र को ठीक करे । जैसा कि मैंने कहा है, मुख्य मंत्री ने बहुमत दल का नेता होने के बावजद वास्तविकता और समय की गम्भीरता को समझ कर यह कदम उठाया और इसके लिये मै उनको धन्यवाद देता हू । (व्यवधान) ।

आज उत्तर प्रदेश की पापुलेशन करीब पौने नौ करोड है । उत्तर प्रदेश को केन्द्रीय सरकार की तरफ से विभिन्न प्रकार की जो सहायता दी जा रही है, वह अन्य स्टेट्स के मुकाबिले मे बहुत ही कम है, जिस के कारण वहां की बैकवर्डनेस लगातार बढ़ती चली जा रही है और वहा की हालत अच्छी नहीं हो पा रही है । कुछ सुधार तो जरूर हुआ है, लेकिन वह उस स्टेट की पापुलेशन को देखते हुये पर्याप्त नहीं है । मुख्य मत्री ने "फिनान्स कमीशन" के सामने यह सुझाव दिया था कि बिजली, रोड्स और एंजुकेशन आदि के लिये केन्द्रीय सहायता के सम्बन्ध मे, केन्द्रीय आउटले के सम्बन्ध मे, एक नेशनल पर्सपेक्टिव होना चाहिये, क्योंकि यह नेशनल इन्ट्रेस्ट मे नहीं है कि देश मे एक प्रदेश तो पिछड़ा हुआ रहे और दूसरा प्रदेश आगे बढ़ जाये । जब "एप्रोच ऑफ दि फिफ्थ प्लान" पर डिस्कशन होगा, तो मैं इस सम्बन्ध मे अपने विचार प्रकट करूंगा, लेकिन इस समय मे केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार को इस ओर सहानुभूतिपूर्वक ध्यान देना चाहिये ।

आज हमारे यहां खेती के बाद दूसरे नम्बर की सबसे बड़ा इडस्ट्री हैंडलूम है । केन्द्रीय सरकार ने हैंडलम इडस्ट्री की तरफ थोड़ा ध्यान जरूर दिय है । लेकिन मै निवेदन करना चाहता हू कि मै अभी अपने क्षेत्र मे आ रहा हू । मेरे पास ये वीवर्स के कार्ड हैं उन्हे कई महीनो से सूत नही मिला है ।

MR. SPEAKER: I do not want to limit the debate, but the the scope of the Bill is very limited, namely the conferment of powers of the State Legislature to make laws, on the President. It is a technical thing. It is not a general debate that we are having now. We have had it already We are not discussing the Proclamation now. We have already approved of the Proclamation. Now, the question is whether powers should be conferred on the President or not, and the hon. Member may say whether he supports it or opposes it. This Bill only seeks to authorise conferment of powers on the President to make laws

श्री नरसिंह नारायण पांडे उत्तर प्रदेश मे जो एडवाइजरी कौंसिल बनने जा रही है, उसको हमारी समस्याओं की तरफ विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है । लेकिन मैं महसूस करता हू कि एडवाइजरी कौंसिल को इस बात पर भी विचार करना चाहिये कि जिला-स्तर विकास के लिये, ग्रासरूट प्लानिंग के लिये, हमारे काम करने के तरीके मे क्या परिवर्तन किया जाना चाहिये और केन्द्रीय सरकार के आदेशो को किस तरह कार्यान्वित किया जाये । इसके लिये यह जरूरी है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आज डेमोक्रेसी को एक्सटेंडिड किया जाये, जिसके अन्तर्गत जिला स्तर पर ब्लाक प्रमुखो, एसेम्बली और कौंसिल के मेम्बरो आदि जनता पार्लियामेंट के मैम्बरो आदि के प्रतिनिधियो की एक जनरल बाडी बनायी जाये । इस प्रकार जिला स्तर पर एक एक्सीक्यूटिव कौंसिल बना कर वहां के डेवलपमेंट और प्लानिंग के सब साधनो का

[श्री नरसिंह नरायण पांडे]

समन्वय किया जाये, हैंड्ज आफ डिपार्टमेंट जिले में हैं उनको विभिन्न कौंसिलस का सेक्रेटरी बनाया जाये और इस कौंसिल को पावर दे कर जिला स्तर पर डीसेंट्रलाइजेशन किया जाये । बहुमत दल के नेता ही की शक्ति दी जाये कौंसिल बनाने की । इस समय फाइनेन्शल हैण्ड बुक के अनुसार लारी पावर्स डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अन्दर निहित हैं । डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट फाइलों में इतना व्यस्त कि जिले की शासन व्यवस्था को क्या कहें, किसी तरह का कोई प्लानिंग सक्सेसफुल हो नहीं पाता है और वह तब तक सक्सेसफुल हो नहीं पायेगा, जब तक फाइनेन्शल हैण्ड बुक को चेन्ज नहीं किया जायेगा और डिस्ट्रिक्ट की चुनी हुई कौन्सिल को पावर नहीं दिया जायेगा, यानी थ्री-टायर गवर्नमेन्ट नहीं बनाई जायगी । मेरा स्पष्ट तौर पर कहना है कि डिस्ट्रिक्ट लेविल पर एक डिस्ट्रिक्ट कौन्सिल बनाई जाय---चुने हुए मेम्बरों की । जैसे यहां पार्लियामेन्ट है और कौन्सिल आफ मिनिस्टर्ज है, उसी तरह से एक एक्जीक्यूटिव कौन्सिल बना कर उन को तमाम पावर्स दी जायें । जो विभागाध्यक्ष हैं, उन को एक्जीक्यूटिव कौन्सिल का सैक्रेटरी होना चाहिये और सारा काम उन सैक्रेट्रीज के द्वारा चलाना चाहिये । डी० आई० जी० की पोस्ट की कोई जरूरत नहीं । इस खर्चे को कम करना चाहिये ; देश में आज खर्चे में कमी करने की जरूरत है और प्रधान मंत्री ने चार सौ करोड़ रुपये की कमी करने की तरफ इशारा किया है । जब तक जिले के आधार पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पावर का विकेन्द्रीकरण नहीं किया जायेगा, चाहे उस के लिये कांस्टीचुशनल अमेण्डमेन्ट करना पड़े और जब तक चुने हुए नुमाइन्दों के हाथ में शक्ति नहीं दी जायगी, डिस्ट्रिक्ट कौन्सिल का निर्माण नहीं किया जायेगा, एक्जीक्यूटिव कौन्सिल बना कर उन को पावर नहीं दिया जायगा और उस कौन्सिल को पूरे हाउस के प्रति जिम्मेदार नहीं ठहराया जायगा, तब तक सही तरीके से वह डमोक्रेसी जिस की हम कल्पना करते हैं, जिस को हम चाहते है कि ग्रास-रूट तक बिल्कुल पहुंच जाय, वह पूरा नहीं हो पायेगा । इस लिये मैं कहता हूं कि आज "एक्सटेण्डेड डेमोक्रेसी" की जरूरत है, "लिमिटेड डिक्टेटरशिप" की जरूरत नहीं है । जो विधेयक आया है---मैं उस का स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि ऐसी व्यवस्था की जाय कि जिले के स्तर पर जितने कानून और कायदे हैं उन का ठीक तरीके से इम्प्लीमेन्टेशन हो सके ।

डा० गौविन्द दास रिछारिया (झांसी) : अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव गृह मंत्री जी ने पेश किया है, मैं उस का समर्थन करता हूं । उस के साथ साथ भारत सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह जो देश का सब से बड़ी आबादी का प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, यह हमारी पिछली योजनाओं में पिछड़ गया है, जब हम जनप्रतिनिधियों से बात करते है---उत्तर प्रदेश के या वहां के अर्थ-शास्त्रियों से बात करते हैं, तो उन का कहना है कि पिछली योजनाओं में योजना व्यय जितना प्रति व्यक्ति होना चाहिये था, उत्तर प्रदेश में उतना नहीं हुआ । उस के कारण प्रति व्यक्ति आमदनी उत्तर प्रदेश की कम हो चुकी है और इसी के कारण वहां इण्डस्ट्री या बिजली आदि भी कम हो गई है । बहुत लम्बा चौड़ा प्रदेश है, उस के अन्दर भी पहाड़ी क्षेत्र---बुन्देल खण्ड का इलाका या पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो भाग है, वह और अधिक पिछड़ गया है, इस वजह से जहां मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं वहां आप से यह भी आशा रखता हूं कि यह ऐसा समय है जब कि पांचवीं योजना बनने जा रही है---पांचवीं योजना का स्वरूप सारे देश में तैयार हो रहा है, तो जो पिछली गल्ती हो गई है उत्तर प्रदेश के साथ या जो पिछली योजनाओं में उस के साथ अन्याय

हुआ है उस को पूरा करने की कृपा भारत सरकार करे ।

हमारी लगभग आठ-दस योजनायें भारत सरकार के पास पड़ी हुई हैं । सिंचाई की और बिजली की, उन को तुरन्त स्वीकृत कर के उन पर काम करने की आवश्यकता है । उत्तर प्रदेश को खुशी हुई थी कि एक एटामिक पावर स्टेशन उस के लिये स्वीकृत किया गया था, किन्तु उस पर अब तक काम शुरू नहीं हुआ । उस पर शीघ्रता से काम शुरू किया जाय । आज बुन्देल खण्ड का हिस्सा बहुत पिछड़ा हुआ है.....

अध्यक्ष महोदय : जरा बिल के रेलेवेन्स के साथ बोलते जाय, तब तो मैं सुनता जाऊंगा । थोड़ा सा बिल के बारे में जिक्र करें और उस के बाद दूसरी बातें लायें, दो बातें और जोड़ दें तो मैं चुप रहूंगा । लेकिन आप तो बिलकुल उधर चले गये ।

डा० गोविन्द दास रिछारिया यह जो बिल आया है मैं उस का समर्थन करता हूं । इस के साथ-साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक ऐसा आदर्श हमारी संस्था ने और हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री ने उपस्थित किया है कि आज तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ । हमारी पार्टी बहुमत में वहां पर थी लेकिन अगर प्रदेश के हित में वहां की व्यवस्था में कुछ कमी आ गई थी, पी० ए० सी० का जो उपद्रव हुआ वह किसी तरह बढ़े न, इस के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया और यह एक आदर्श उपस्थित किया —हमारे मुख्य मंत्री ने इस तरह से उस का समर्थन करते हुए और उन को धन्यवाद देते हुए जैसा मैंने आप से निवेदन किया, उत्तर प्रदेश के जो ऐसे हिस्से हैं जो पिछड़े हुए हैं उन की ओर ध्यान दिया जाय । आज जब कि भारत सरकार ने यह निश्चय किया है कि जो पिछड़े हुए हिस्से हैं उन को समानता के स्तर पर लाना चाहिए तो हम आप से यह आशा करते हैं कि बुन्देलखंड, उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले और पहाड़ी क्षेत्र जो हैं उन के लिए इस तरह की अलग से योजनाएं बनाएं जिस से कि उन का स्तर हमारे प्रदेश के और पूरे भारत के तमाम दूसरे हिस्सों के बराबर के स्तर पर आ जाय । आज जब कि हरियाणा के प्रत्येक गांव में सड़क और बिजली पहुंच चुकी है, उत्तर प्रदेश के तीन और चार हजार की आबादी के ऐसे गांव हैं जहां सड़क नहीं है, बिजली नहीं है । इन को समान स्तर पर लाने लिये के आप को विशेष व्यवस्था अपनी योजनाओं में करनी पड़ेगी ।

13.26 hrs.

[MR DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

आप को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में कुछ नदियों को लेकर विवाद चल रहा था—सिंचाई के सिलसिले में बेतवा नदी पर राजघाट योजना तैयार हुई, उस का शिलान्यास भी 14 अप्रैल को प्रधान मंत्री जी ने किया, लेकिन उस का काम अभी तक बन्द है । हम आशा करते हैं कि उस का काम शीघ्र शुरू किया जायगा । इसी तरह से हम्मीरपुर और बांदा में भी दो बांध बनाने तय हुए थे—मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में, उन पर भी शीघ्र काम शुरू करने की आवश्यकता है । जैसा मैंने कहा—एटामिक पावर स्टेशन एक हमें मिला, लेकिन उस का काम रुका हुआ है, उस को भी शीघ्र शुरू कर ने की आवश्यकता है । झांसी जिले में पारीछाबांध पर एक थर्मल पावर स्टेशन मिला हुआ है राज्यपाल महोदय ने उस का एस्टीमेट बना कर भेजा है और प्लानिंग कमीशन से कहा है कि उसे शीघ्र—स्वीकृत किया जाय ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: I hope you will be an hon. Member of one of these consultative committees and that is the proper forum for you to mention all these things. Kindly conclude now.

श्री झारखण्डे राय (घोसी) : उपाध्यक्ष महोदय, आज की स्थिति जो उत्तर प्रदेश मे पैदा हुई है, उस के मुख्य सात कारण रहे हैं। क्रान्तिकारी भूमि सुधार की तरफ से बिलकुल उदासीनता और उस को ठण्डे मे छोड देना। चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर इतना शोर-शराबा करने के बाद भी चुप्पी साध लेना। भ्रष्टाचार का चरमसीमा पर पहुच जाना। छात्र असन्तोष इंजीनियर्स की हडताल बुनकरों की दुरवस्था, और आखरी और सब से बडा कारण— पुलिस का विद्रोह। इन सात घटनाओं मे उत्तर प्रदेश की आज यह स्थिति पैदा है। मैं अपनी बात कुछ सुझावों से शुरू करना चाहता हू जो इस स्वीकृति के पहले जरूरी है और जिस के बारे मे मुझे सन्देह है कि भारत सरकार दबाना चाहती है। पी० ए० सी० विद्रोह हमारे देश के इतिहास में आजादी के बाद एक अद्वितीय घटना है। इस को उतनी ही गम्भीरता से लेना चाहिये, इस के लिये केन्द्र से हाई-प्राव होना चाहिये और अगर इन के पीछे कोई राजनीतिक दल है, कोई तत्व है, कोई विचारधारा है, कोई व्यक्ति है तो उस की भी जाच होनी चाहिये। अगर नही, यह स्वत एक विद्रोह था तो उस की भी स्थिति स्पष्ट होनी चाहिये अखबारों मे, जनता मे, राजनैतिक क्षेत्रों मे, तरह तरह की बाते इस विषय मे कही जाती है। इन सब का निराकरण अन्तिम रूप मे भारत सरकार को करना चाहिये।

कमलापति जी की सरकार गई, वह अनिवार्य और अपरिहार्य हो गया था। इस स्थिति मे उस का रहना सडांध को और चलाना था। लेकिन मेरा सुझाव यह थी है कि पी० ए० सी० विद्रोह के नाते यह सरकार अन्तिम रूप से और तात्कालिक रूप से हटाई गई तो चीफ सैक्रेटरी को क्यों नही हटाया गया और डिप्टी होम सैक्रेटरी क्यों रखे गये? आई जी और डी आई जी की क्या कोई जिम्मेदारी है या नही? केवल कमलापति जी की सरकार को एस्केपगोट बनाया जा रहा है। इनको भी हटाया जाना चाहिए और इसका विश्लेषण होना चाहिए—यह मेरा सुझाव है। साथ ही पुलिस वालों पर दमन बन्द होना चाहिए। दमन से स्थिति का समाधान हरगिज नहीं होगा। आज स्थिति पूरे देश की कई माने मे बद से बदतर होती जा रही है। पी०ए०सी० के 1600 आदमी आज बन्द है, उन्हें छोड देना चाहिए। जिनके ऊपर प्राइमा फेसाई, प्रादर्शन मे केस सिद्ध हो उन पर केस चले भारत के कानून के मुताबिक तो उसमे कोई आपत्ति नही है। साथ ही पुलिस वालों को भी सगठन बनाने का अधिकार होना चाहिए एक सीमित दायरे के अन्दर। कर्मचारियों के लब्ध प्रतिष्ठ नेता श्री पी०एन० सुकुल और श्री शिव कुमार मिश्र आज जेल में बन्द है डी०आई०आर० म। मैं फिर कहता हू कि डी० आई० आर० का इस्तेमाल समाज विद्रोहियों के खिलाफ होना चाहिए न कि उनके खिलाफ जो कि सरकार के विरोधी है ...... (व्यवधान)

मैं एक बात स्पष्ट रूप मे बतला दू कि राष्ट्रपति शासन जनप्रिय शासन का कोई सब्स्टीट्यूट या विकल्प ही हो सकता। उत्तर प्रदेश म कांग्रेस पार्टी का बहुमत है, आज भी है जिसका किसी ने विरोध नहीं किया है, चुनौती नही दी है इसलिए उत्तर प्रदेश की कांग्रेस पार्टी को अधिकार है और साथसाथ कर्त्तव्य भी है कि अपनी सरकार वहां पर बनाये और भारत सरकार को उसके लिए सुविधा देनी चाहिए। कमलापति उस सरकार के नेता रहे या कौन रहे, यह आपका आन्तरिक मामला है उसमें हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर यह स्थिति नहीं

[श्री झारखण्ड राय]

हो सकती है तो फिर विधान सभा को मोअत्तल करने की बात नहीं हो बल्कि उसे समाप्त करना चाहिए और तत्काल नया चुनाव कराना चाहिए ।

एक बात और है । 1972 में शासक पार्टी ने नारा दिया था विशेष रूप से कि भारत के प्रदेशों में स्थायित्व के लिए यह आवश्यक और अनिवार्य है कि एक पार्टी का बहुमत रहे । यह मुख्य केन्द्रीय नारा था जिसके इर्द गिर्द 72 का सूबों का चुनाव शासक पार्टी लड़ी लेकिन आज वह नारा गलत सिद्ध हो गया । एक पार्टी का शासन रहते हुए, एक पार्टी का बहुमत रहते हुए करीब करीब हिन्दुस्तान के 6 सूबों में अस्थायित्व पैदा हो गया है । पार्टी टूट रहे हैं, खंड खंड हो रहा है । आंतरिक कलह चरमसीमा पर है इसलिए यह धारणा सही नहीं है । धारणा यह होनी चाहिए कि कार्यक्रम की एकता अगर अनेक दलों में हो तो वह स्थायित्व ला सकते हैं । एक पार्टी जिसमें सिद्धान्तहीनता हो, जिसमें कार्यक्रम की एकता न हो, जहां पर परस्परविरोधी विचारधारा के लोग हों, उस एक पार्टी का शासन रहते हुए स्थायित्व नहीं लाया जा सकता है ।

इन शब्दों के साथ मैं इन मांगों को दोहराते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार अपने इन कर्तव्यों का पालन करने में किसी तरह की कोताही नहीं करेगी ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have to explain once again the scope of the Bill. Under the President's rule, the power to make laws for UP rests with this Parliament. Because Parliament may not have the time, this Bill seeks to confer that legislative power on the President and the President will do it in consultation with the hon. Members of this House and the other House. That is the scope of the Bill. If you want this, support it if you do not want this, oppose it. If you go into the various things going on in UP, it is irrelevant and it takes a lot of time. These matters were discussed when approval of the President's Proclamation was made and the forum will be when the consultative committee is set up.

श्री मधु लिमये (बांका): मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है ।

मैं आपका निर्णय चाहता हूं इस बात पर कि क्या सदन को इस विधेयक पर विचार करने का अधिकार है और इसलिए मैं आपका ध्यान दफा 356 और दफा 12 की ओर दिलाना चाहता हूं । इस समय स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा निलंबित है, उसको बर्खास्त नहीं किया गया है और मेरी राय में इस सदन में इस विधेयक पर तभी बहस हो सकती है जब विधान सभा को पहले बर्खास्त किया जाये । जब तक विधान सभा बर्खास्त नहीं होती है 356 धारा में जो प्राविजन्स दिए गए है उन पर अमल नहीं हो सकता है ।

दफा 356 (1) (सी) में कहा गया है :

"Make such incidental and consequential provisions as appear to the President to be necessary or desirable for giving effect to the objects of the Proclamation, including provisions for suspending in whole or in part the operation of any provisions of this Constitution relating to any body or authority in the State:"

अब मैं आपका भाष्य चाहता हूं —

What is the meaning of the expression "any body or authority in the State"?

[श्री मधु लिमये]

क्या इसमें विधान सभा (लेजिस्लेचर) भी आती है ?

Does it include the Legislature of UP?

आप संविधान की धारा 12 भी देखें जिसमे "राज्य" की परिभाषा की गई है । यह आर्टिकल इस प्रकार है

Part III. Fundamental Rights, article 12:

"In this Part, unless the context otherwise requires, 'the State' includes the Government and Parliament of India and the Government and the Legislature of each of the States and all local or other authorities within the territory of India or under the control of the Government of India."

इसमे लेजिस्लेचर का उल्लेख अलग से किया गया है एथारिटीज मे कौन सी आती है ? लाकल एण्ड अदर एथारिटीज ? एथारिटी और बाडी मे विधान सभा नही आ सकती है क्योकि आर्टिकल 12 मे व्याख्या दी गई है राज्य की और कही डेफनीशन हो तो आप सदस्यो मे, मत्री महोदय से पूछे ला मिस्टिर को बुलाये, एटार्नी जनरल को बुलाये इसकी परिभाषा होनी चाहिए कि राष्ट्रपति के जो अधिकार हैं वह क्या अधिकार है ?

"for suspending in whole or in part the operation of any provisions of this Constitution relating to any body or authority in the State:"

The question is whether the "Legislature" is included in the expression "any body or authority in the State".

मेरा कहना है कि जो 12वी दफा अभी आपको पढ़कर मैंने सुनाई उसमें लेजिस्लेचर का बिल्कुल अलग से उल्लेख किया गया है । इसका साफ मतलब है कि एथारिटी बाडी मे लेजिस्लेचर नही आता है । लोकल बाडी आ सकती है, म्युनिसिपैलिटीज आ सकती है, कोई बोर्डस वगैरह बनाये जायें जैसे एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, पचास इस तरह की बाडीज रहती हैं वह आ सकती है । अभी तक किसी ने इसको चुनौती ही नही दी, आपने एक नया सिलसिला शुरू किया, विधान सभा को निलबित करना, लेकिन जब विधान सभा का अस्तित्व है तो उसका कानून बनाने का अधिकार हम छीन नही सकते है । इसलिए यह बहस तभी आगे ला जाये जब इसमे आप निर्णय देगे कि बाडी और एथारिटी मे विधान सभा आ सकता है या नही, उसको निलबित किया जा सकता है या नही और उसके अधिकारो को समद ले सकती है या नही ।

MR. DEPUTY-SPEAKER. Now Shri Madhu Limaye says this is a point or order To me it is a constitutional objection to this Bill It is his point that this Bill cannot be accepted by this House It is a constitutional objection It has nothing to do with the order of the House as such

SHRI MADHU LIMAYE Why not?

MR DEPUTY-SPEAKER Kindly do not get excited.

SHRI MADHU LIMAYE I am not getting excited I am only trying to get the Rules of Procedure enforced

MR DEPUTY-SPEAKER Your constitutional objection is there. It is expected that the Minister will reply to that. After the House has discussed this point it is for the House to decide it.

SHRI MADHU LIMAYE: It is for you to give the ruling.

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is an established procedure that the Chair off hand here should not give any

legal or constitutional pronouncements on any constitutional or legal point. It should not.

SHRI MADHU LIMAYE: You reserve your ruling.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Therefore, when a constitutional objection is raised, it is necessary for the Chair to hear the other side also.

So, your point is there. Let us go on with the debate....

SHRI MADHU LIMAYE: How can the debate go on?

MR. DEPUTY-SPEAKER: You tell me how it cannot go on.

श्री मधु लिमये : आप रूल देखिये 376 (1) । मैं आप को बता रहा हू कि यह डिबेट कैसे आगे नही चल सकती । पौइट आफ आर्डर के बारे मे रूल यह है :

"376(1) A point of order shall relate to the interpretation or enforcement of these rules or such Articles of the Constitution as regulate the business of the House and shall raise a question which is within the cognizance of the Speaker."

मेरा केवल आप से यही निवेदन है कि मैं ने यह कहा है कि जब तक विधान सभा अस्तित्व मे है, कानून बनाने के उन के अधिकारो को हम नहीं ले सकते । आप विधान सभा बर्खास्त कीजिये तब कानून बना सकते हैं । अगर आप का कहना यह है कि अथौरिटी में, चौदी में विधान सभा आती है तो आर्टिकिल 12 के आधार पर मैं ने साबित किया है ·

Legislature is an entity, distinct from a body or authority.

इसलिये आप को निर्णय लेना है । मंत्री जी को आप सुनिये और आपनी रूलिंग रिजर्व रख सकते हैं । इसलिये जब तक आप का निर्णय नहीं आता तब तक यह बहस नहीं चल सकती ।

श्री नरसिंह नारायण पांडे . उपाध्यक्ष जी, मैं ने लोक सभा की पुरानी प्रोसीडिंग मंगायी हैं । पजाब असैम्बली का भी इसी तरह से सस्पेंशन हुआ था और इसी तरह का कांस्टीट्यूशनल पौइंट श्री यू० एन० त्रिवेदी ने उठाया था । उस पर उस समय के लोक सभा के अध्यक्ष ने एक रूलिंग दी थी जिस मे उन्होंने कहा था, जैसा अभी आप ने अपनी रूलिंग में कहा कि यह कांस्टीट्यूशनल मामला है, उस के इटरप्रीटेशन का सवाल है और अगर इस प्रश्न को आप को उठाना है तो सदन के बाहर हाई या सुप्रीम कोर्ट में जा कर उठा सकते हैं, उस को चैलेंज कर सकते हैं । लेकिन यहा पर कास्टीट्यूशनल आस्पेक्ट पर स्पीकर कोई रूलिंग नही दे सकते हैं ।

उस के बाद भी बहुत सी विधान सभाये सस्पेंड की गईं और उसके बाद वहा पर ऐडवाइजरी काउन्सिल्स फ़र्म की गयी । लेकिन यह प्रश्न केवल उसी समय उठा था और उस समय जो रूलिंग दी थी वह मैं आप को बताना चाहता हू । आप ने बिल्कुल सही रूलिंग दी है और मैं समझता हूं कि यह कोई ऐप्रोप्रिएट समय नही है ।

श्री मधु लिमये आप उस निर्णय को उद्धृत कीजिये ।

SHRI K. C. PANT: Sir, I have been trying to follow the argument of my. friend, Shri Limaye.

Firstly, on questions of constitutional interpretation, I thought that the normal practice was that the task of interpreting the Constitution was left to the courts. It is not done by Parliament. But that apart, here, the House has already approved the Proclamation. It is in the course of

[Shri K. C. Pant]

the Proclamation that the President declared that the powers of the State Legislature shall be exercised by or under the authority of Parliament.

This is a consequential piece of legislation. The Proclamation has already been approved. That power has already been transferred. The House has already approved the transfer of power from the State Legislature to Parliament. So, if at all, a point lay, it was at the time the Proclamation was discussed. Today, the point does not lie at all. It is irrelevant. All that we are doing is to see that there is a Consultative Committee and, where the Parliament will not have the time, the President can take that power from Parliament. Therefore, this cannot arise at this stage.

SHRI B. R. SHUKLA (Bahraich): Sir, the constitutional bar to the discussion of the Bill should have been raised when the Bill was sought to be introduced. Once it has been introduced, the discussion can be raised only with respect to the merits and demerits of the Bill.

Article 356 (1) (b) clearly provides that, once the President has made a Proclamation, then Parliament will make provision that the powers of the Legislature of the State shall be exercisable by or under the authority of Parliament. The wordings in article 356(1)(b) are not confined only to the case where the Legislature is under a State of suspension: this is a general provision and extends to the case of suspension and also to dissolution.

As the hon. Minister has pointed out, we have now come to the stage of article 357, which is only a consequential provision. Once the Proclamation has been approved by the House, there is no option but to make a provision for legislative process by the President.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now I am concerned with the order of the House. The order is whether we can go on with this discussion or not. That is your main point, Mr. Limaye. Although for supposition sake I admit that these may be a Constitutional point in what you are pressing—there may be—, I am now concerned with the order of the House. I think, your objection is rather late. The Minister has pointed out that the President's Proclamation has laid down specifically, which this House has adopted, that the powers of the Legislature of the State shall be exercisable by or under the authority of Parliament. This is the decision of the House. We have done it. If this is not regular, it is for the court to decide. As far as the House is concerned, this has been done. That is number one.

Secondly, I think, the next occasion when you could raise this objection was when the Minister moved this for consideration. Anyway, it is late now. We have already adopted and this is only a consequential measure. Therefore, I think, we can go on with this discussion....

श्री मधु लिमये : बोडी ओर अथौरिटी को व्याख्या नही करेंगे ?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Limaye, this is a legal interpretation.

श्री मधु लिमये : आप अपनी रूलिंग रिज़र्व कीजिये।

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is most reckless for anybody sitting in the Chair without going deep into the matter to give a legal interpretation to a thing like this, I cannot go into it. I am concerned with the

order of the House at the moment. Kindly do not press this.

Shri Bishwanath Roy.

श्री विश्वनाथ राय (देवारिया) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति को उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल की विधियां बनाने की शक्ति प्रदान करने के विधेयक का मैं स्वागत करता हूं । इस की आवश्यकता उस समय पैदा हुई जिस समय भारतीय गणतन्त्र मे उच्च आदर्श उत्तर प्रदेश मे वहां की सरकार ने बहुमत मे होते हुए स्थापित किया । 425 मे से 272 का बहुमत रहने पर भी अपनी सरकार ने इस्तीफा दिया और उस के बाद राष्ट्रपति शासन लागू हुआ । आवश्यकता क्यो पड़ी इस के विस्तार मे जाने की आवश्यकता नही है, लेकिन यह अवश्य है कि उस शासन के बाद जो विधान बनेगा वह तो बने, लेकिन उस के लिये यह है कि उसके कार्यान्वयन मे कुछ ऐसे लोगो का हाथ भी होना चाहिये जो सीधे जनता से संबंधित हो, और न केवल उत्तर प्रदेश मे एक प्रदेशीय स्तर पर सलाहकार समिति बने, बल्कि जिले के स्तर मे ऐसी समितियो का गठन हो । इस कारण जो असेम्बली निलंबित की गयी है उस को ऐसी दशा मे रहने देना चाहिये और असेम्बली के सदस्य ससद के सदस्य या ब्लाक प्रमुख जिले की सलाहकार समिति मे हो । प्रदेश के स्तर पर आप चाहे जिस रूप मे सलाहकार समिति बनाये । इसलिये असेम्बली को डिजाल्व नही करना चाहिये, बल्कि उस को कायम रखना चाहिये । और यह इसलिये भी आवश्यक है कि प्रदेश में सारी बातो को ले कर हर एक जिले से लोग लखनऊ नही पहुच सकते । जिलो मे बहुत से ऐसे प्रश्न उठते हैं जिन पर जिला स्तर पर ही विचार किया जाना चाहिये । मिसाल के लिये सवाल पैदा हुआ कि सूखे के बाद क्या स्थिति है । एक सप्ताह पहले मैं अपने जिले मे गया तो मुझे मालूम हुआ कि एक सुपरवाइजर कोआपरेटिव्ज का जो था उसने खाद लिया और ब्लैक मे बेच दिया । जनता के पास वह खाद नही गया । इसी तरह से कई जगह हरिजनों पर अत्याचार होते हैं । उनको सुनने वाला कोई नहीं होता है । इस कारण भी मैं चाहता हू कि एडवाइजरी बाडीज होनी चाहिये । हरिजनो, शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्स ट्राइब्ज पर जो बीत रही है वह चीज गांव, तहसील आदि के स्तर से उठे और प्रदेश के स्तर तक जाए तथा दूसरी बातें जाए, इसलिये मैं चाहता हू कि असेम्बली को डिसाल्व किया जाए बल्कि गांव से प्रतिनिधि ले कर, ब्लाक के प्रमुख के आधार पर तथा असेम्बली के मेम्बरों तथा पार्लिमेंट के मेम्बरो को लेकर उनकी सलाहकार समितिया जिले जिले मे होनी चाहिये ताकि सरकारी कर्मचारी तथा अधिकारी जो गड़बड़िया आदि करते हैं वे सामने आती रह सकें । मैं सभी को दोष नहीं देता हूं लेकिन उस तरह के अधिकारी जैसे मैं ने आपको बताया है कि खाद लेकर ब्लैक मे बेच देते है, जनता को वह नही दिया जाता है, सुपरवाइजर ने स्टाक लिया और उसको ब्लैक मे बेच दिया उनकी बातें बाहर आनी चाहिये जिलो के अधिकारियो तक पहुचना चाहिये और उनको पहुचाने के लिये एडवाइजरी बाडीज का होना जरूरी है । राष्ट्रपति जी को कानून बनाने का अधिकार दिया जा रहा है लेकिन जनता के कष्टो को सामने लाने के लिये यह जरूरी है कि विधान को सीधे जड तक जनता के स्तर तक हम ले जाए, प्रदेश के स्तर तक ले जाए । इसके लिये मैं समझता हू कि अनेक स्तरो पर सलाहकार समितिया होनी चाहियें । जो इलैक्टेड बाडीज हैं जो इस वक्त काम कर रही है उनको ज्यो का त्यो काम करने रहने देना चाहये । वे बन्द नही होनी चाहिये ।

एक दो छोटी मोटी बातें मैं और कह देना चाहता हूं । डा०के०एल०राव जो इरिगेशन

[श्री विश्वनाथ राय]

एंड पावर के मिनिस्टर हैं उनके सामने एक रिपोर्ट आई थी कि देवरिया जिले में सिर्फ 37 प्रतिशत फसल पर सूखे का बुरा असर पड़ा है। इसको देख कर बड़ा आश्चर्य हुआ। 27 जून को एक बार वहां थोड़ी सी वर्षा हुई थी। उसके बाद जुलाई 26 तक पानी नहीं बरसा। फिर भी यह बताया गया कि केवल 37 प्रतिशत पर बुरा असर पड़ा है। उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से न जाने कैसे यह बना दिया गया कि केवल 37 प्रतिशत फसल को हानि हुई है। इस तरह से जो गलत रिपोर्ट आती हैं उनके ऊपर ध्यान दिलाने के लिये तथा राष्ट्रपति शासन में अच्छी तरह से काम हो मैं चाहता हूं कि एडवाइजरी बाडीज बनें और वे तब तक काम करती रहें जब तक दूसरा इलैक्सन नहीं हो जाता। राष्ट्रपति शासन को चलते रहने देना चाहिये भारतीय लोकतंत्र में एक नया यह एक्सपैरिमेंट है। यह तब तक चलना चाहिये जब तक नए चुनाव हो नहीं जाते। संविद की सरकार जब वहां थी और उसके होते हुए लोक सभा के जो चुनाव थे और हमने सफलता पाई थी सारे देश में, वैसे ही राष्ट्रपति शासन में जब चुनाव होंगे तो फिर हम अपना बहुमत ला कर यह साबित कर देना चाहते हैं कि भारतीय लोकतंत्र मजबूत हो चुका है और देश के शासन को वह अच्छी तरह से चला सकता है।

श्री महा दीपक सिंह शाक्य (कायमगंज): उपाध्यक्ष महोदय, पिछले चार वर्षों से उत्तर प्रदेश में 272 सभासदों द्वारा चलने वाले नपुंसक दुःशासन का 13 जून को अन्त हुआ और राष्ट्रपति जी ने उत्तर प्रदेश में अपने शासन की घोषणा की। उस घोषणा पर गत सप्ताह बहस हुई और भिन्न भिन्न विचार व्यक्त किए गए। हमारे उधर बैठने वाले साथियों ने यह नहीं बताया और न बता सके कि मुख्य मन्त्री महोदय जिनका इतना भारी भरकम बहुमत था, 272 सदस्य उनके साथ थे फिर भी उनका मंत्री मंडल कार्य करने में सक्षम क्यों नहीं हुआ था, क्यों उनको त्यागपत्र देने के लिए विवश होना पड़ा? मैं समझता हूं कि यह उनकी अयोग्यता का एक जीता जागता उदाहरण था। मैं उस में विस्तार से जाना नहीं चाहता हूं। यहां पर आज जो चर्चा चल रही है वह उस पर है जो श्री पंत ने विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत किया है जिस में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति जी को अधिकार दिया जाए कानून बनाने का। मैं समझता हूं कि किसी भी देश के प्रशासन को स्वस्थ बनाने के लिए चार बातों की आवश्यकता होती है। उन चार बातों को पूरा करने में उत्तर प्रदेश सरकार अभी तक किस हद तक सफल हुई है, उन पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालकर आपको बताऊंगा कि मैं इस विधेयक का क्यों विरोध कर रहा हूं।

पहली बात यह है कि प्रशासन स्वस्थ हो इसके लिए यह आवश्यक है कि देश में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो। सुरक्षा दो प्रकार की होती है। एक बाह्य और दूसरी आन्तरिक। बाह्य सुरक्षा के बारे में कुछ कहने का यह अवसर नहीं है। उत्तर प्रदेश में आन्तरिक सुरक्षा कैसी रही यही मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरी समझ में यह नहीं आया कि यहां पर प्रशासन लोकतंत्र का था या पुलिस तंत्र का था? मैं इसकी केवल एक मिसाल आपको देना चाहता हूं। अभी सात आठ की रात का किस्सा है। थाना सहावर, जिला एटा, उत्तर प्रदेश का यह किस्सा है। वहां दो दारोगा, चार कान्स्टेबिल पांच छः आदमियों को साथ लेकर, कुल बारह आदमियों लेकर रामनगर के मौजे में बारह बजे गए और वहां उन्होंने डकैती डाली सत्तर लाख की। मैं स्वयं मौके पर होकर आया हूं। औरतों से भी उन्होंने छेड़छाड़ की। डकैती के बाद जब लोगों ने देख भाल करनी शुरू की तो उनको छः साइकिलें, एक पुलिस की टोपी, कारतूसों के खोल उनको मिले। साइकिलें किसी और की हो सकती थीं, बदमाशों की हो सकती थीं

लेकिन दोषी की डकैतों को हो सकती थी, यह यकीन नहीं किया जा सकता है। उसके बाद छः बजे एक थानेदार और एक सिपाही खुद पहुंचे और कहा की हमारी छः साइकिलें जो तालाब पर रखीं थी आपके यहां हैं वह देदें। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो हमारा क्या बिगाड़ लोगे, पुलिस वालों के खिलाफ दफा 395 और 397 का मुकदमा दर्ज किया गया है जो एस०पी० द्वारा दर्ज किया गया। लोगों ने देने से इन्कार किया और कहा कि हम नहीं देंगे तब तक जब तक रसीद नहीं दे दी जाती, पुलिस वालों ने साइकिलों की रसीद देने से इन्कार कर दिया और लौट गये।

MR DEPUTY-SPEAKER: If you are opposed to this Bill because of absence of security etc. I would like to know what you would have done in U.P.? You have taken 5 minutes Please conclude.

श्री महादीपक सिंह शाक्य : मैं वही पर आ रहा हू डकैती की जाच के लिए डी० एस० पी० मौके पर गये, उन्होंने मुद्दई को धमकाया लेकिन उन्होंने कहा कि रसीद दें तब हम देंगे नही तो नहीं देंगे। नतीजा यह हुआ कि पुलिस वालों ने षडयंत्र रचा मुद्दई के नाम 378 का केश दर्ज किया गया और झूठे मुकदमे दर्ज किये। मैं माग करता हू कि जो पुलिस वाले अपराधी हैं उनको ससपेंड किया जाए।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Are you opposed to legislative powers being given to the President? That is the main question....

AN HON. MEMBER: Obviously.

MR DEPUTY-SPEAKER: Are you opposed to these legislative powers being given to the President?

श्री महादीपक सिंह शाक्य : मै समझता हूं कि आन्तरिक सुरक्षा लाने के लिए राष्ट्रपति शासन सक्षम नहीं हो सकता है। इसी लिए मैं इसका विरोध करता हूं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, conclude please.

श्री महादीपक सिंह शाक्य : मैं समझता हू कि जो बहुमत वाली वहां पर सरकार थी उसको चाहिए था कि वह नए नेता का चुनाव करती और ऐसा अगर वह नही कर सकती थी तो उसको चाहिए था कि आप विधान सभा को भंग करके वहां पुन: चुनाव कराते और नई सरकार को जन्म देते।

स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्था के बारे मे भी मै एक शब्द कहना चाहता हू। व्यक्ति स्वस्थ नही होगा तो राष्ट्र भी स्वस्थ नही हो सकता है। हमने देखा है कि गरीब आदमी जब अपने बच्चों को अस्पताल ले जाते हैं इलाज के लिए तो अगर ए टी एस का इंजेक्शन भी लगाना होता है तो उनको कह दिया जाता है कि बाजार जाओ और खरीद कर ले आओ। ये जो सब चीजे होती हैं इन पर नियंत्रण करने के लिए चाहे आप समितियां बनाएं, चाहे पार्लियामेंट की कमेटी बनाएं, और चाहे कोई और व्यवस्था करें लेकिन इसका असली इलाज तो वहां नई सरकार के माध्यम से ही, उस के जन्म से ही हो सकता है।

रक्षा, जन स्वास्थ्य, और भूमि विकास को दृष्टि मे रखते हुए प्रशासन को अच्छे ढग से चलाया जाय। इसलिए मै चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश मे शीघ्र ही चुनाव कराए जायें और उसके बाद वहां लोकतंत्रीय सरकार को काम करने का अवसर दिया जाये।

14 00 hrs

SHRI NARSINGH NARAIN PANDEY: Sir, I rise on a point of clarification. I have referred to certain proceedings of 1966, as I have quoted and Shri Madhu Limaye wants me to quote which is here in my hand. Should I read it out?

MR. DEPUTY-SPEAKER: In what connection is it? I think I have given my ruling. And that was over.

श्री कृष्ण चन्द्र पांडे (खलीलाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम इस बिल के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के अधिकार सौंप रहे हैं। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

उत्तर प्रदेश नौ करोड़ का प्रदेश है और आज वहां पर राष्ट्रपति शासन है। जिन कारणों से राष्ट्रपति शासन वहां लागू किया गया, उन कारणों मे तो मैं नही जाना चाहता, परन्तु मैं माननीय गृह मन्त्री से यह आग्रह जरूर करना चाहता हू कि इस बात की तरफ भी ध्यान दिया जाय कि उत्तर प्रदेश मे पुलिस ने किन कारणो से विद्रोह किया। क्या यह सही है कि वहा का प्रशासक वर्ग निकम्मा था और उस के निकम्मेपन के कारण पुलिस ने विद्रोह किया ? यह बात तो समझ मे नही आती है कि सरकार तो चली जाये लेकिन वे उच्चाधिकारी उन्ही पदो पर बर-करार रहें, जिन पदो पर उन के रहते हुए उत्तर प्रदेश मे पुलिस का विद्रोह हुआ। मुख्य मन्त्री ने लोकतन्त्र का एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया, जो विश्व मे अपने ढग का पहला था। लेकिन जहा तक मेरी जानकारी है, आज भी वे बड़े अधिकारी और पुलिस अधिकारी अपने पदो का उसी तरह दुरुपयोग कर रहे है, जिस के कारण उन्होने पुलिस को विद्रोह करने के लिए मजबूर कर दिया था। मैं माननीय गृह मन्त्री से यह भी जानना चाहता हू कि पी०ए०सी० का जो पुनर्गठन किया जा रहा है, उस मे जो सुधार किये जा रहे हैं, क्या उन मे वही अधिकारी सम्बन्धित नही हैं, जिन के रेजीम मे पुलिस ने विद्रोह किया।

यह कहा जाता है कि अगर उत्तर प्रदेश में सरकार बनी रहती, तो दूसरे प्रदेशो मे पुलिस विद्रोह की आग भड़क सकती थी। पुलिस के जिन जवानों ने विद्रोह किया था, क्या वे आज खुले-आम यह नही कह रहे हैं कि हम में यह ताकत है कि हम सरकार को बदल सकते हैं ? सरकार के पास इस का क्या जवाब है ? पुलिस के जवानों को निकालने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। इससे आग और भी भड़केगी। सरकार जहां विद्रोह के दोषी पुलिस के जवानो को निकाला, वहा उन को पुलिस के अधिकारियों को भी निकालना चाहिए था, जिसके अधीन पुलिस के जवान काम कर रहे हैं। मैं यह बात यही खत्म कर देता हू, लेकिन मैं गृह मन्त्री महोदय से यह मांग करता हू कि वह उन पुलिस अधिकारियो के बारे में भी विचार करे, जिन के हाथ मे पुलिस का प्रशासन था।

अभी तक उत्तर प्रदेश की बड़ी उपेक्षा हुई है। इस समय पांचवी पंच-वर्षीय योजना का प्रारूप बनने जा रहा है और यह दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे प्रदेश मे कोई सरकार नही है। उत्तर प्रदेश की विभिन्न समस्याओ को हल करने के लिए उत्तर प्रदेश की ओर से जो योजनायें भेजी गई हैं, उन को स्वीकार किया जाना चाहिए और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस सम्बन्ध में जो धनराशि मांगी थी, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को देखते हुए वह दी जानी चाहिए।

उत्तर प्रदेश के एडवाइजरी बोर्ड ने इस जिलो को पिछड़ा हुआ और सूखाग्रस्त घोषित किया है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बस्ती जिले के बगल के, जहा मेरा संसदीय क्षेत्र है, सारे जिले सूखाग्रस्त घोषित किये गये हैं, लेकिन बस्ती जिले को, जो बहुत गरीब और उपेक्षित जिला है, सूखाग्रस्त घोषित नही किया गया है। मैं नहीं जानता कि इस के क्या कारण हैं ?

उत्तर प्रदेश औद्योगिक दृष्टि से भी बहुत पिछड़ा हुआ है। उस के औद्योगीकरण के लिए जो प्लान आया है, उस को स्वीकार किया जाना चाहिए।

जहां तक पुलिस विद्रोह का सम्बन्ध है, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। देवरिया में एक पुलिस कोतवाल था, जिस को लेकर उत्तर प्रदेश की विधान सभा में एडजार्नमेंट मोशन रखा गया और उस को ले कर देवरिया बन्द हुआ। गवर्नर महोदय देवरिया जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। राष्ट्रपति शासन मे वह व्यक्ति गोरखपुर में फिर कोतवाल हो गया है। उस ने वहां पर फिर वही स्थिति पैदा कर दी, जिस के कारण गोरखपुर मे भी आन्दोलन की नौबत आ गई है।

उत्तर प्रदेश मे एक बहुत भयंकर समस्या खड़ी हो रही हैं और एक ओर हड़ताल होने जा रही है और एक उत्तर प्रदेश के इंजीनियर्स फिर स्ट्राइक पर जा रहे हैं। सरकार को उन की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए।

उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को देखते हुए वहां के पंच-वर्षीय योजना के बजट को स्वीकार करना चाहिए। वहां पर जल्द से जल्द एक जनप्रिय सरकार बना कर इस अफ़सरशाही को समाप्त करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री मधु लिमये (बांका) उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक की योजना है कि साठ लोगों की एक कमेटी बने और जो भी कानून राष्ट्रपति के द्वारा पारित किये जायेंगे, उन के बारे मे इस कमेटी की राय ले ली जाये। मैं चाहता हूं कि अगर मन्त्री महोदय मानें, तो इस विधेयक मे एक संशोधन किया जाये। विधान सभा का काम केवल कानून बनाना ही नहीं हैं। जो जनता की समस्यायें हैं, प्रशासनिक मामले हैं और लोगों की शिकायतें हैं, उन पर भी विधान सभा विचार करती है। जब इस कमेटी में इन सवालों को लेते हीं हैं, तो फिर मन्त्री महोदय कानून में ही इसका प्रावधान क्यों नहीं करते हैं कि इन मामलों के बारे में भी राष्ट्रपति इस कमेटी की सलाह लेगा?

जिस किसी सूबे में राष्ट्रपति शासन हो और इस तरह की कमेटी बने उस कमेटी की बैठकें दिल्ली में न हो कर उस सूबे की राजधानी में की जाये। जनता को पहले से पता चले कि कमेटी की बैठक हो रही हैं, ताकि कमेटी के सदस्यों के पास अवाम के लोग अपनी शिकायतें ले कर जा सकें।

एक प्रैस विज्ञप्ति के द्वारा इस कमेटी की कार्यवाही की रपट जनता के सामने रखनी चाहिए और अखबार वालों को भी देनी चाहिए।

बहुत दफा कानूनों के तहत नोटिफिकेशन और आर्डर निकाले जाते हैं। जैसे, मैंने सुना है, और अखबारों मे भी आया है कि राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद मल्ला-बसूली के बारे मे एक आर्डर या नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इस कमेटी को इस के ऊपर भी सोचने का मौका मिलना चाहिए क्योंकि आज कल के कानूनों मे बहुत बड़े पैमाने पर प्रशासन को अधिकार दिया जाता है, नियम आदि बनाने का और नोटिफिकेशन निकालने का, तो इस कमेटी को इस के ऊपर भी चर्चा करने का मौका मिलना चाहिए।

इस वक्त उत्तर प्रदेश के ऊपर नौ संकट हैं—नवग्रह। एक है सूखे का संकट, दूसरा है बाढ़ का संकट, तीसरा है बिजली का संकट, चौथा सूत के अभाव का संकट। मऊ आजमगढ़ मे और मुबारकपुर मे, बनारस मे सूत का इतना अभाव है कि सारे बुनकर बेकार हो रहे हैं। सूत के बारे में मैं ऊब गया हूं, हजार दफे सवाल उठाया, लेकिन बुनकरों को बिल्कुल सूत नहीं मिल रहा है। तो सूत के अभाव का

[श्री मधु लिमये] .

संकट है । पांचवा संकट है-उत्तर प्रदेश का बहुत ज्यादा शहरीकरण है, बड़े - बड़े कारखाने चाहे वहां न हो लेकिन छोटे-छोटे उद्योग वहां बहुत हैं । मुरादाबाद में बर्तन का उद्योग है, फिरोजाबाद में चूड़ियों का उद्योग है और इन तमाम छोटे उद्योग वालों को कोयला नहीं मिल रहा है । मेरे पास पत्र द्वारा बहुत सी ऐसी सूचना आ रही है कि कोयले के अभाव में उन के कारोबार बन्द हो रहे है । तो पांचवां कोयले के अभाव का संकट है । छठवां संकट है दाम-वृद्धि का । सातवा सकट है भ्रष्टाचार का । आठवां संकट है दमन नीति का । 17 तारीख को उत्तर प्रदेश बन्द का कार्यक्रम था । वहा हमारे दल के दो हजार आदमियों को गिरफ्तार कर लिया भारत सुरक्षा कानून के तहत ।.. (व्यवधान) . वह फेल नहीं हुआ । खुद जिन एजेंसियों के ऊपर आप हावी हैं वह भी मानती है कि एफेक्टिव नो था फुली एफेक्टिव नही था । फिरोजाबाद जैसे छोटे शहरो में हड़ताल मुकम्मिल रही । लेकिन उस मे मैं नहीं जाना चाहता । मै मांग करना चाहता हूं कि इन दो हजार आदमियो को जिन को आप ने गिरफ्तार किया है उन को क्या आप छोड़ेंगे ? तो यह आठवां दमन का संकट है । और नवां सकट है केन्द्रीय कांग्रेस के अनियंत्रित प्रशासन का सकट । उस से उत्तर प्रदेश को राहत कब मिलेगी ? इसलिये मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हू कि जो पहली बैठक हो वह लखनऊ मे की जाये और इन नौ सकटों के ऊपर उस मे विचार किया जाये । मन्त्री महोदय इन बातों के ऊपर सफाई दें ।

SHRI B. R. SHUKLA (Bahraich): Under very painful circumstances and most reluctantly, I extend my support to the passage of this Bill. Day in and day out, in this House we are condemning the increasing role of the bureaucracy. But it is most unfortunate that while having a very stable government in a House of 425 members, we have handed over the rule of that biggest State of this big country to three persons who happen to be the top most advisers of the Government.

Shri Kamlapatiji, like God Shiva in mythology, has taken the poison under his threat. - It stands to the credit of Central Government that it has not spared its most beloved leader in whom this party has full confidence. That should silence the criticism of the Opposition parties when they say that whenever we get an opportunity we see to it that a State Government of a party other than Congress is dethroned. We have the power and capacity to ask our own men to resign and come down from the seat of power when national security and interest demand it. Whatever his fault, at least on this occasion Shri Tripathiji has done the right thing; when he saw there was trouble in his State which was likely to spread and engulf the entire country, he resigned from his seat and the Central Government advised the President to impose President's rule in the State which he did.

SHRI DASARATHA DEB (Tripura East): Why are you maintaining idle members of the Assembly? Dissolve it.

SHRI B. R. SHUKLA: There was a Ministry in Bengal headed by the United Front. On a legal pretext, they were refusing to resign. But here is a Chief Minister who has resigned without any hesitation. We are bound to support this Bill, as a stop gap arrangement. I want to voice my feelings that the Committee to be formed by the Parliament should not be merely an advisory body but it should function effectively by making it at least a convention that the voices of the Members who constitute the Consultative Committee are heard with the effect and rigour

as the voices of the members of the State legislature were heard by the Ministry concerned.

So far as I have been able to understand, there is no provision in the Constitution for forming a consultative committee. Article 357 provides that the Parliament can make a provision conferring the power on the President to make laws for the State and the President in his turn can delegate this authority to anybody subject to certain conditions. There is no provision for constituting a consultative committee, which should be consulted. The power should be exercised by the President himself or by persons to whom this power is delegated. I want to be enlightened on this point. When a certain provision is not made in the Constitution, by implication it is forbidden. Whatever is not expressly provided for is impliedly prohibited. Though on principle I welcome the formation of a consultative committee as envisaged in the Bill, I want to be assured of its constitutional validity

I want to conclude by saying that everything has not become better or happier by the imposition of the President's rule. Bureaucracy by its nature is wooden and unresponsive and opposed to progress. If this arrangement continues for any period longer than is absolutely necessary and justified in the circumstances, it would put back the wheels of progress and would revert us to the days of the Britishers.

श्री स्वामी सहजानन्द जी (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं क्यों कि जब राष्ट्रपति शासन है तो बहुत जरूरी है कि कमेटी बने । पर साथ साथ मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी उच्च अधिकारी अगर खराब होता है, जैसा अभी एक माननीय सदस्य ने कहा, उस को दंड नहीं देंगे और कमेटी बनने के बाद वही अधिकारी बैठे रहेंगे तो क्या लाभ होगा ? मुख्य मंत्री और उन का मंत्रिमंडल अगर ठीक न होता तो किस तरह गवर्नमेंट विफल होती ? मैं पहले भी कह चुका हूं कि, अगर मुख्य मंत्री अच्छा हो, ईमानदार हो, तो गवर्नमेंट कैसे विफल हो सकती है ? यह लीपापोती बिलकुल गलत है कि मुख्य मंत्री अच्छा था ।

एक आदमी मुट्ठी भर चना चुराता है, खाने के लिये लेता है तो उस को हथकड़ी डाल दी जाती है और जो अधिकारी बड़े बड़े भ्रष्टाचार करते हैं, करोड़ों की कोठिया बना ली है, मिनिस्टरों ने घर भर लिए, करोड़ों की सम्पत्ति बना ली उन को एक को जेल नहीं भेजा गया तो कैसे भ्रष्टाचार मिट सकता है ?

मैं चाहता हूं कि जब वहां पर एक पार्टी का बहुमत है तो यह नहीं है कि उत्तर प्रदेश में सब बेईमान हैं, उन के अंदर भी ईमानदार आदमी होंगे उन को शासन सौंपिए । ईमानदार आदमियो के लिये तो राजा महेन्द्र प्रताप ने कहा था जो इतना बड़ा देशभक्त है कहा कि सरकार ने नहरें बनाई, बिजली बनाई, सड़के बनाई पर इंसान नही बनाए । मैं पूछता हूं क्यों नहीं वहां ईमानदार आदमी को उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठाया जाता है ? मैं ने राष्ट्रपति महोदय से बात की, राष्ट्रपति महोदय भी बड़े दुखी है कि वहां बड़ा भारी भ्रष्टाचार है । पर आज राष्ट्रपति महोदय की बात कौन सुन रहा है ? क्यों नहीं हथकड़ी डाली जाती है उन अधिकारियों को और उन मिनिस्टरों को जिन के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं ? उन पर क्यों नहीं मुकदमा चलाया जाता है ? आरोप गलत भी होते हैं मगर क्या अभी तक कोई भी मंत्री पिछले 25 साल मे बेईमान नही था ? क्यों और कहीं भी नहीं उस को हथकड़ी डाली गई ? क्यों नही उन को जेल में भेजा गया ? सही बात तो यह है कि जो कमेटी कहेगी उस पर अमल कौन करेंगे वहीं अधिकारी करेंगे । मेरा कहना है कि वहां पर कांग्रेस में विधायकों का बहुमत है, इसलिये ईमानदार आदमियों

[श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी]

को गद्दी पर बिठा कर जनता की सरकार बनाई जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री चंद्रिका प्रसाद (बलिया) : माननीय उपाध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश हमारे देश का सबसे बड़ा भाग है, आज राष्ट्रपति शासन होने के कारण वहां पर अधिकारियों का राज्य है, जिस की वजह से जो जनवादी रूप इस क्षेत्र का होना चाहिये, वह दिखाई नहीं पड़ता है। पिछले दो महिनों के अन्दर हमारे क्षेत्र में जो बाढ़ आई और सूखा पड़ा, यदि वहां लोकप्रिय सरकार होती, जनता की सरकार होती तो जिस तरह से वह काम करती, उस के मुकाबले इन अधिकारियों के काम करने का तरीका भिन्न है।

वर्तमान परिस्थितियों में संविधान के अन्तर्गत वहां अधिक से अधिक डेमोक्रेटिक स्वरूप बन सके, इस दृष्टि से आप जो कमेटी बनाने जा रहे है, मैं उस का स्वागत करता हूं। लेकिन साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक डेमोक्रेटिक स्वरूप बनाने की दृष्टि से वहां जिला स्तर पर कान्सिल बनाई जाये। यदि जिला स्तर पर सम्भव न हो तो रिजन-वाइज जा सकती हैं, प्रदेश स्तर पर हो और विशेषकर जो प्रदेश के तीन चार बैकवर्ड-पाकेट्स है, उन में इस प्रकार की कमेटी होनी चाहिये जब हमारे यहां लोकप्रिय सरकार थी, तो उन क्षेत्रों की अलग अलग विकास परिषदें बनाई गई थी, लेकिन ये सक्रिय नहीं हो सकी। इस लिये इन उपेक्षित क्षेत्रों के लिये कन्सलटेटिव कमेटीज जरूर होनी चाहियें, जो कम से कम महीने में एक बार वहां बैठें और उन क्षेत्रों की समस्याओं पर विचार करें। इस लिये मैं चाहूंगा कि प्रदेश स्तर पर, उपेक्षित क्षेत्रों के बैक-वर्ड पाकेट्स के लिये, रिजनवाइज या जिला स्तर पर ऐसी कमेटी बनाई जाय ताकि उन का अधिक डेमोक्रेटिक स्वरूप बन सके।

हमारे अन्य साथियों ने कहा कि कानून बनाना ही हमारा काम नहीं है, बल्कि जो हमारी समस्यायें हैं, हमारे हरिजनों पर अत्याचार होता है, सूखा पड़ता है, बाढ़ आती है, हमारे अधिकारी वहां काम करते हैं, लेकिन जितनी तेजी से पब्लिक वर्कस करते है, अधिकारी उतनी तेजी से नहीं कर पाते। इस लिये यदि उन क्षेत्रों में कन्सलटेटिव कमेटीज बन जाये तो अधिकारियों के सहयोग और कन्सलटेटिव कमेटी के सहयोग से जो काम होगा – वह ज्यादा सक्रिय होगा और उस का ज्यादा डेमोक्रेटिक स्वरूप होगा।

SHRI PILOO MODY (Godhra): I am really surprised that this Bill has come before Parliament. It seeks to confer on the President the power of the Legislature of the State of Uttar Pradesh to make laws. I cannot understand how there can be two bodies representing the legislature of a State. We are now going to have a body over here legislating on behalf of the State and we are having a body in U.P. which has been left in suspended animation I do not know why. If it is the intention of this government to continue President's rule in U.P. all the way up to the elections, the Assembly should be dissolved. Otherwise, I can only suspect that this is a rather crooked way of keeping a lot of Congress MLAs and MLCs with *bhatha, bhusa*, daily allowance and what have you at the cost of the people We have constantly been hearing about our serious resources position, we have been constantly hearing about cutting down non-productive administrative expenditure and, on the other hand, we have these two Assemblies in suspended animation for months on end, fulfilling no purpose at all, doing no work at all, and yet being paid daily allowances and what have you of I do not know how many crores of rupees. The result is that one seriously questions the sincerity and

the *bona fides* of this Government if it continues to do something like that.

I am not even clear about the constitutional validity of a suspended legislature. I think that there can be at best two opinions, that if not completely *ultra vires* of the Constitution whether' there should be a suspended legislature. Either the legislature is there, which has a majority and which can function as a majorfty; and if that majoirty cannot function, and no other majority can function within that legislature, it should be dissolved.

AN HON. MEMBER: A Congress innovation.

SHRI PILOO MODY: Yes, it is a Congress innovation. It is one more method that the Congress has devised in order to plunder money from the people in order to feed its own party. I am sorry, I have to stay these hard words in a debate here on the floor of Parliament. Normally I reserve these remarks only for my public speeches. But on this occasion I have to bring that element into this House in order to impress on the Minister and on the Government that they are fooling nobody by this process at all

The fact of the matter is that there is a constitutional crisis not only m UP but all over the country where you have a party which has sought and got a massive mandate, or a so-called massive mandate, and won umpteen seats in Parliament and in the Legislatures by hook or crook. and yet they cannot hold these people together for the purpose of governing. I am seriously worried that if through the process of majorities we are not in a poisition to rule this country, are we going to rule it through the process of minorities? Therefore, it is highly questionable whether a legislature where a majority exists and which still demonstrates its inability to rule, whether such a legislature should be continued at all in the overall interest of democracy. I feel that you must go back to the people and seek a fresh mandate as a result of which there will be a new Assembly. If that new Assembly also functions in a similar fashion, I say that also should be dissolved.

I think that the manner in which the Congress has gathered its members, the manner in which it has collected people, the manner in which it has collected mandate is today being laid bare by what has happened m UP, Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat and so many other places. I, therefore, think that they have forfeited their right to rule over this country. It is now merely a matter of people. It is a matter of a few days or months before the people will give their verdict on the Government. I only appeal to the Home Minister that before they are thrown out, do not ruin the condition of the country any further, or the constitutional procedures of this country.

SHRI K C. PANT: The Speaker and you, Mr. Deputy-Speaker, if I may respectfully say so, rightly limited the scope of this debate It was only your inattention, perhaps, which enabled Shri Piloo Mody to go into the merits of whether or not the President's Rule should have been imposed. Passing references were made to the fact that the Congress was in a majority in UP but, in spite of the fact that there was a majority, President's Rule was imposed on that State.

This debate has taken place earlier in the House and I do not want to go over the same ground. The Home Minister has dealt with it here. But when my hon. friend, Shri Piloo Mody, speaks of the massive mandate and other friends speak of our majority of 272, they must give us a credit at least of having considered

[K. C. Pant]

this point beforehand. It is not as though this is a very complicated matter. It is obvious that the State Government or the Chief Minister of U.P. or the Government at the Centre realised fully well that we had a majority of 272 when the President's Rule was imposed. In spite of that, the Chief Minister of U.P. and the members of the Cabinet recommended the imposition of the President's Rule.

I can understand the criticism of the Government both then and now. But I cannot understand how this is sought to be portrayed as a matter of serving the self-interest of the Congress in the State. If there is anything to establish that the Stae Government, the State Chief Minister, acted only out of a consideration of national interest, that he was impelled by a consideration of national interest, to come to a decision in the matter, nothing else can establish it more than the fact that he chose to recommend the President's Rule. Mr. Patel says, party interest....

SHRI PILLO MODY: You are twisting what I said.

SHRI K. C. PANT: I am replying to the points raised by hon. Members. These points were raised when you were not here.

Mr. Patel says, this was to serve the party interest. If Mr. Patel had been governing the country, would he have served....

SHRI H. M. PATEL: (Dhandhuka): I did not say that.

SHRI K. C. PANT: He whispered, I think.

SHRI PILOO MODY: You don't reply to my points and you reply to what he whispered.

SHRI K. C. PANT: I have to listen to his whispers. You never whisper. If you have to say anything, we can hear even in the corridor of the Lobby.

It was implied by Shri Bhattacharyya, for instance, in his speech right in the beginning, that this was done to serve the party interest. Now, unfortunately or fortunately, no other party in the country has been able so far to gain control of the Government here or to run the Government at the Centre and also to have Governments in the States. But if a party does have a Government at the Centre and in the States and the situation similar to one which arise in this case arises, then only a party which will place national interest above the party interest will take an action which the Congress hss taken in this case.

SHRI PILOO MODY: I am not blaming you for imposing the President's Rule. I am blaming you for putting the Legislature in suspension and paying all your Members T.A./D.A., etc.

SHRI K. C. PANT: I was under the impression that there were many political parties in the Opposition and Mr Piloo Mody did not speak for all of them. He only come at the fag end of the debate. He does not know what the debate has been before he came here. He is not aware of those facts.

MR. DEPUTY-SPEAKER: That is one of the problems with him.

SHRI K. C. PANT: So, this is all I have to say in regard to the basic question of majority and massive mandate which had been raised here. I can only say that a specific situation arose and a pecific answer was given.

The points which had been raised cover a wider field. Mr. Pandey said that U.P. should not be allowed to lag behind. Somebody else raised the question of the Fifth Plan allocation for U.P. I do not want to go into details now. But I can assure them that the State Government is continuing to bear in mind the past

needs, the present needs and the future needs of the State. The continuing projects and the need to develop backward areas about which Dr. Richaria spoke, all these things, are being considered and discussions are going on with the Planning Commission just now.

SHRI PILOO MODY: In any case it is outside the scope.

SHRI K. C. PANT: Outside whose scope?

SHRI PILOO MODY: Your scope.

SHRI K. C. PANT: In the sense that the Home Ministry has a co-ordinating role when a State is under President's rule. I happen to know something about it. Ordinarily it would have been outside my scope.

It is quite true in a general sense to say that if U.P., the largest State in India and with a large population, lags behind, it becomes a drag for all the States, it becomes a drag for the country. Therefore, it is in the interest of the nation that U.P.'s backwardness should be taken care of. The whole country will not grudge if U.P. is allowed to be pulled up economically speaking, and that applies to other States also like Bihar, Assam or any other State which is in a similar position. So, I would agree that, looking at it from the interest of the nation as a whole. U.P. should be enabled to make economic progress and where it has lagged behind, to catch up with the rest of the country.

There was some reference to the need to have district level advisory councils. He referred to extension of democracy. I do not want to get into a discussion of the three-tier system at this stage. We do have a three tier in the form of Zila Parishad, State Government and Parliament. But during President's rule also, we would like to have these advisory committees at the district level with MLAs, MPS, etc., and in the situation now prevailing....

SHRI PILOO MODY: Panchayats also?

SHRI K. C. PANT: You do not know the position. The position there is that new elections have been started for Zila parishad. They have proceeded upto a point. Block Pramukhs have been elected. One representative each has to be elected from the Blocks and co-option has to take place. After that, the Zila Parishad elections have to be held. The idea is that there should be advisery committees and I agree with the suggestion... (*Interruptions*). Non-officials pose a difficulty. I would like to explain that having a non-official head poses the difficulty as to who should be chosen. On that point you can have further discussion. I myself think that it would pose difficulties to make a choice in the present circumstances, and perhaps having the DM would be less controversial, although one may prefer to have non-official...

SHRI NARSINGH NARAIN PANDAY: There is a circular from the Government of India in which gradation has been fixed and accordingly a non-official should be the Chairman. The gradation of MPs and MLAs is higher than the District Magistrate. Why should the District Magistrate preside, when M.Ps., MLSs and other non-officials are there?

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): During the Conference of Ch Whips in Simla, this question was raised and a unanimous decision was taken that a non-official should be the Chairman.

SHRI K. C. PANT: Both of my friends are speaking about normal situation. There were States including—it was not U.P., it was some other States; I forget the name of the State now—where the District Magi-

[Shri K. C. PANT]

strate.... (*Interruptions*). A point was raised and I am trying to deal with it. You have widened the scope of the debate luckily.

SHRI PILOO MODY: I am against these committees altogether.

SHRI K. C. PANT: I was only explaining that some State had DM as the head of the Zila Parishad. At one stage, U.P. also had it during Chaudhuri Charan Singh's time if I remember right. Later on, this point was raised. I konw this. But the point is that, just now, the elections are not complete, therefore, whom to select just now will obviously pose a practical problem. That is all I want to say.

Dr. Richhariya raised the question of the atomic power plant. There also I would simply say that discussions are going on with the Planning Commission about the allocations for this projcet and the Department is making efforts to see that the work which is already started proceeds quickly.

Mr. Jharkhande Rai raised many questions. He and Pandeyji referred to the problems of yarn to the weavers. I do not want to go into that now. I am told that the situation has eased in relation to the past and if there are difficulties, we would like to do everything possible to ease those difficulties and I would be very happy to discuss this problem both with my friends perhaps outside the House. I do not want to take the time of the House on this.

The questions of corruption, students and prices raised are not relevant only in the context of U.P. These are wider questions.

He referred to the pen-down strike or whatever it is by the engineers in U.P. I must say that I am rather surprised by the action of the engineers. They know that in U.P. just now there is a power shortage. They also know that although the rainfall has luckily improved in the Eastern U.P. still we have not had rainfall in the catchment of Rihand. The level of water in Rihand is just 806' which is a precarious level from the point of sustained power production. Therefore, on the whole, the power position is precarious in U.P. just now. In this situation, the need of the hour is for all concerned to put their shoulders to the wheel and see that power production and generation is carried out at the maximum efficiency and that nothing is allowed to be wasted. This is the need of the hour and in this situation, if the engineers in U.P. say that they will go on strike because the Punjab Government has suspended the Chairman of their Electricity Board, I just cannot see the logic of it and I cannot see how such an action can be justified. It is for the Punjab Government to take action against their officers and the Punjab Government has proceeded against this officer, as far as I know, on charges of corruption. His house has been searched and certain things have been recovered Now, what are we getting into? If the Punjab Government takes action against an officer who it regards, as corrupt, if the engineers in U.P. go on strike over this, it is completely unjustified and I hope my hon. friends will raise their voice against this kind of a thing at a time when public interest in UP requires that power generation and distribution is at its best. If the engineers using it as an excuse go on strike, it is something to be condemned and I would request all the sections of the House to raise their voice unequivocally on this matter.

श्री झारखंडे राय : मैं ने इस स्ट्राइक की बात नहीं की थी, बल्कि पहले वाली स्ट्राइक की बाबत कहा था।

SHRI K. C. PANT: Only a couple of minutes more and I have finished.

He raised the question of the Police Association having the limited right

of association. That right is already there. Only the constitution of the Police Association has to be approved by the Government. This is the condition. Otherwise, the right is already there.

Some specific instances were referred to by my friend from the Jana Sangh. I cannot offhand say anything about these specific instances.

Now, Mr. Madhu Limaye said that general matters should be discussed by the Consultative Committee.

(व्यवधान) जनसंघ ने डकैती कहा की है। यह तो डकैती की बात आयी है। अगर आप ने कुछ किया हो तो बता दीजिये।

He referred to the Consultative Committee discussing general matters also. He knows even now it is the practice for them to discuss general matters and this is an advisory committee and it is not a legislative body. It only advises the President and so, Shri Shukla said that there was a constitutional point involved I am not an expert on this and I cannot say whether any constitutional point is involved I would have thought that it is well within the powers of the Parliament to constitute such a Consultative Committee There is absolutely nothing wrong in it. It is advisory in character. Shri Limaye suggested that proceedings of the committee should be publicised; usually they are publicised; and if the House agrees that the Government can give some kind of a handout to the Press at the end of each committee meeting that can easily be arranged, but if each Member gives out a version of what happened then it creates difficulties.

SHRI MADHU LIMAYE: Draft also should be approved by the Committee.

SHRI K. C. PANT: How can you approve it? It takes time. There is no controversy about it. If somebody has something to say, it will be reflected in the handout. Everybody has ample opportunity to say what he likes.

Then reference was made by him to the *bandh* by the socialist party. He said 2,000 people are in jail. I do not want to deride his effort either. It is a fact that the *bandh* failed; and the *bandh* has been a failure throughout the State. I know his party alone is not to be blamed; certain other parties were there which backed out.

श्री मधु लिमये : बन्द हुआ या नहीं यह उत्तर प्रदेश की जनता को मालूम है। दो हजार लोगों को आप ने भारत सुरक्षा कानून के तरह बन्द कर रखा है आप उन को छोड़ेंगे कि नहीं।

SHRI PILOO MODY: It is a valid question that if the *bandh* has failed then why did they take 2,000 people in jail?

SHRI K. C. PANT: After I reply, Sir, Shri Madhu Limaye will save me from my friends, because, Sir, Piloo Mody is now forcing me to give the figure. I do not want to belittle the effort that they made. At the insistence of these friends I give the figure, it is only 176. That is a small figure in relation to 2000, but in relation to the effort that the party has made, and in spite of being let down by some other parties, it is considerable. Sir, I do not really know why this *bandh* is being organised. The State Government is doing its level best, taking action against hoarders, against profiteers etc. From hoarders, near about 50,000 quintals of foodgrains have been recovered. Raids are being organised all over the State and those who comes from the State will bear me out in what I say, from their experience in their own districts.

[Shri K. C. PANT]

These *bandhs* only disrupt the normal distribution system. By this, you only add to the difficulties of the people. Without disrupting there can be protests. In this House you are protesting every day. The country takes notice of it.

श्री जमु लिमये : 9 करोड़ के लिये 90,000 क्विंटल । यह इन का हिसाब है ।

SHRI K. C. PANT: If somebody else had said it, then I could have accepted it. If Shri Limaye has said it, there is usually something in it and it would have come to the notice of all people in the whole country. And this is the right forum in which you protest. Certainly you criticise and protest. Who is saying 'no' to this. Why organise *bandhs* and things like, where by you disturb the distribution of grains at this stage? Sir, we are Gandhians and we have been brought up in Gandhian traditions. How do you expect us to be like C.P.M. people?

I think you are looking at the clock and you are feeling somewhat impatient. I do not want to waste the time. I would only like to say that the basic objective, with which the present agitation would have been started, has been achieved. Now, the P.A.C. is being re-organised, the C.I.D. organisation is also being looked into. In the State, the administrative officers are being screened. Senior officers are being sent for from Delhi whenever the State Government asks for them. Efforts are being made to speed up the developmental projects and various areas of priorities have been marked out, like giving power connections for energising tubewells and diesel sets are given where power cannot be taken. The question of giving home stead land for harijans is under consideration. And most definitely, in regard to Harijans, the State Government has been particularly vigilant after the President's takeover. My hon. friend knows that in recent weeks no incidents of atrocity committed on harijans have come to notice.

With these words, I hope that the House will agree with this Bill without any reservation.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill to confer on the President the power of the Legislature of the State of Uttar Pradesh to make laws, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now we shall take up the clauses. There are no amendments to clauses 2, 3 and 1, the Enacting Formula and the Title.

The question is:

"That clauses 2, 3 and 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clauses 2, 3 and 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI K. C. PANT: Sir, I move:

"That the Bill be passed."

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill be passed."

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA (Begusarai): Mr. Deputy-Speaker, Sir, by now, it is clear that the President's Rule is really the party rule in the State.

The President's Rule is functioning most brazenfacedly for the aggrandisement of the interests of the ruling party. The discredited set-up remains more or less intact.

The gentlemen who had gone out by the front door have been again brought in by the back door. And

they continue to dominate the political scene there. I would give you a few examples how the old set-up had been kept intact there. In fact, the old set-up have got now a shield to protect them to do whatever they like. No words can be too strong to condemn this attitude of the Central Government.

Mr. Deputy-Speaker, as I told you earlier I am now giving a few examples on how the old set-up is being maintained there. Shri Kamalapati Tripathi is the Chairman of the Planning Board. Shri Narain Dutt Tiwari is the Vice-Chairman or Vice-President, whatever be the designation, of the Planning Board. Shri J. P. Rawat is the President of the Panchayat Raj Committee. Shri Chaturbhuj Sharma is the Chairman of the Irrigation Commission. Shri Beni Singh Awsati, who was the Minister, in the old set-up, is the honorary Food Advivser to the Governor there. Only during the last week, probably ten days ago, ten members of the ruling party have been made in charge of the so-called campaign for the procurement drive in the State; they have been made divisional-incharge in all the ten Divisions, with full parapphernalia,—cars and all that.

There is another submission that I would like to make. Now, reports are pouring in that raids are being organised on producers and consumers against the rules that have been laid down by Government. Government have laid down rules that every producer can keep with him self 20 quintals and consumers eight quintals. But, now, emergency measures are being used by the corrupt officers to line their own pockets, and raids are being organised to the great oppression of the people there.

I wanted to make only these submissions during the third reading.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): I was expecting the hon. Minister Shri K. C. Pant to say something about the release of the two undisputed leaders of the State Government employees, Shri P. N. Sukul and Shri S. K. Mishra, who were arrested at the time when there was the PAC agitation. I do not call it revolt or mutiny but I call it only PAC agitation. I do not know why they were detained and why they are detained still. I would request the Minister to kindly throw some light on this matter. What was the statement for which they were arrested? They simply said, as some of us also say, that the demands of the PAC employees were just and legitimate. They had said nothing which warranted the application of the DIR, and yet they were arrested under the DIR, and thus the DIR were misused completely. Representations have been made to Government for their release, and I would request the hon. Minister to throw some light on whether they have been released, and if not, the reasons for not releasing them.

Again, 41 persons were arrested under the DIR when they were agitating against the boarders, in Lakhimpur. But the hoarders were not arrested.

MR. DEPUTY-SPEAKER: In what way are these things connected with this Bill?

SHRI S. M. BANERJEE: The State is under President's rule. Where else should I say this? The panchayat is there, of course, but I cannot raise this there. There is no Assembly also. That is why I am raising it here.

SHRI A. K. M. ISHAQUE (Basirhat): And that too in the third reading.

MR. DEPUTY-SPEAKER: That too during the third reading.

SHRI S. M. BANERJEE: He is laughing for the third time now. The first time he laughed because others were laughing. For the second time he laughed because he had realised why people were laughing. Now, he is laughing for the third time because he knows now what laughter is....

SHRI A. K. M. ISHAQUE: Most probably he has committed this to memory.

SHRI S. M. BANERJEE: Anyhow, I am happy that he has started laughing at least.

I was saying that the people arrested in connection with the food agitation should be released immediately. The hon. Minister has asked why there should be *bandhs*, and he has asked why people should not take recourse to democratic methods. I would submit that *bandh* is a democratic method and quite legitimate too. In U.P., in the open market, rice is being sold at Rs. 1.80 per k.g. in the case of the ordinary variety, and atta is being sold at Rs. 2 per k.g Dalda is out of the market completely and it is not available at all. Mustard oil is selling at Rs 9½ per k.g. Ghee which was available at Rs. 14 per k.g. about three months back is now being sold at Rs. 24 per k.g. When people are manifesting their anger at this and they want some reply from the Government, why should there be firing and why should they be arrested? Even the Prime Minister has said that there should be resistance movement in the country. When people start the resistance movement we find that they are arrested under the DIR or there is firing as in Bhopal where seven people have been killed. I would like to have answers to these points from the hon. Minister.

श्री मधु लिमये : उपाध्यक्ष महोदय, मै भी बोलना चाहता हूं। यदि मंत्री महोदय, मेरे मुद्दो का जवाब नहीं देंगे, तो और क्या चारा रह जाता है ? सूबे बार, कौयले की कमी और कुल मिलाकर किसी भी प्रश्न के बारें में उन्होंने जवाब नही दिया है ।

मैं एक और मुद्दा उठाना चाहता हूं । राष्ट्रपति शासन पर बहस होने के बाद मैंने गृह मंत्री को एक पत्र लिखा । मैं ने बैटालियन का नम्बर और पी० ए० सी० के जवान का नम्बर भी दिया । मैं ने यह जानना चाहूंगा कि क्या अखलाक अहमद नाम के जवान को इस लिये नैनी जेल मे नही रखा गया है कि उस ने अफसरो के जानवरों के लिये घास काटने से इन्कार किया और क्या इशाक अहमद नाम के जवान को इस लिये गिरफ्तार नही किया गया कि उस ने एक अफसर के बच्चो को मुफ्त मे पढ़ाने मे, टयूशन देने में इन्कार किया। पत्रा का कोइ जवाब नहीं मिलता है, बहस का जवाब नही मिलता है, वहा विधान सभा नही है । इस स्थिति मे हम लोग क्या करें ।

15 hrs

SHRI K C. PANT. I do not think my friend, Shri Limaye, would have written to me.

श्री मधु लिमये : मैं ने गृह मंत्री को लिखा है, जो बड़े मंत्री है ।

SHRI K C. PANT: I have not personally seen the letter.

श्री मधु लिमये : क्या कुछ कलविटव रसपासीबिलिटी रखत हैं ?

SHRI K. C. PANT:

जिम्मा रखते हैं ।

The point that he had made was really that there were genuine grievances amongst the PAC men. I accept that. I would also like to tell him that various measures have been taken to give them addition facilities to take care of their grievances. It is only out of my deference to your anxiety to limit the scope of the debate that I have not touched on these points. I have full details on the measures we have taken. If you will permit me a minute, I will just

go over the main points. These include a very substantial increase in the welfare fund, more funds for police housing, new tents, extension of medical facilities to families of policemen, more liberal uniforms supply, changes in TA rules to benefit head constables and constables, free food supplied for duty beyond 9 hours as against 18 hours earlier, extension of subsidy on motor cycles to CID, intelligence staff etc.

SHRI MADHU LIMAYE: No liberty.

SHRI K. C. PANT: Liberty is not something which we can give. I am not clear how it is covered by grievances. Does he mean the liberty of those who are arrested? Some have been arrested and disciplinary action has been taken against some. Keeping in mind the unanimous sense of outrage in the House at what had happened in UP. I think the House will take us to task if we do not reimpose discipline in the PAC. I think the whole country will ask us why we did not reimpose discipline. How are you to reimpose discipline unless disciplinary measures are taken? So it is in this light that my friend has to see this. We are not vindictive. We do not want to take any extra measures apart from what is necessary, If we do not take the action necessary, we will again be guilty of dereliction of duty.

He asked for details about drought etc. Again, if you want me to go into it, I can do so. But these are matters which have been discussed in the House before. In the Consultative Committee, we can go into these matters in depth.

The leader of the Congress(O), Shri Mishra—he is not here—said that a certain number of committees had been set up.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI (Patna): He is going to join your party very soon.

SHRI K. C. PANT: Just now he is sitting with you. I do not know what he does tomorow.

I would like to clarify one point. He said that Shri J. P. Rawat and Shri Chaturbhuj Sharma had been appointed by us under President's rule. This is not so. Both of them had been appointed earlier by the elected government.

So far as other things are concerned, he himself is complaining that raids are being organised in a certain manner which is causing harassment. Is it not better that a certain element of non-official association is there at least in some areas? I think he should have welcomed this. Instead he is criticising it. All the time we hear that President's rule is bureaucratic and if some eminent public men are associated with it, I do not think it should lead to any cause for complaint.

I think Shri Banerjee referred to the arrest of Mr. Sukul and Mr Mishra. I do not think that their statements are quite as innocent as made out by Shri Banerjee. If Shri Banerjee himself sees this statement which they made at the time and if he is in agreement that anybody who gets involved in permitting this kind of indiscipline in the PAC should not be allowed to do so....

SHRI S. M. BANERJEE: You kindly read the statement as it came in the newspapers. P. N. Sukul, apart from being a Government servant is also the President of the Federation of State Government employees.

SHRI K. C. PANT: I have understood the point. I am personally of the view that if somebody is a leader of the employees, by virtue of his being a leader. he is more responsible. One could understand some of the failures of the erring employees but when the leader is involved, and if he is found guilty,—I do not know whether this action was taken during the elected State Government's time —and if they were satisfied that he had said something or done something

[Shri K. C. Pant]

which was encouraging indiscipline in the PAC as s leader of the employees, then he deserves less or more punishment? That is the point to be considered. it is a fact that he is leader and that makes it difficult; if he were anybody else it would not have made it so difficult. I hope you appreciate it.

SHRI S. M. BANERJEE: I have not appreciated it at all. Why do you not release him now?

SHRI K. C. PANT: Appreciation has two meanings, I meant the other way. He talked about the high prices and the organisation of bandhs. I was only saying that under the circumstances of today bandhs lead to disruption of distribution and thereby the vulnerable sections are the ones to be affected. Prices will not come down through bandhs. Price resistance—yes; creating an atmosphere against price rise, action against hoarders and profiteers, adulterators—yes. But bandhs disrupt distribution and that is something to be taken note of. If he gives some thought to this he will himself come round and the constructive part of him will respond to what I am saying.

SHRI S. M. BANERJEE: Why not use the DIR against hoarders in Delhi? Why against the striking PAC men?

SHRI K. C. PANT: DIR is being used against hoarders in many parts of the country.... (*Interruptions*) If you want information, I can tell you that in June itself, the Home Minister wrote to the State Governments—not after the President's rule in U.P. that stringent measures should be taken against all hoarders and profiteers and so on and he followed it up by another letter. They asked whether MISA could be used; we said: yes, by all means. Then we wrote a letter that DIR can be used. So, there is no question of giving any quarter to those antisocial elements.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed".

The motion was adopted.

15.11 hrs.

STATUTORY RESOLUTION RE: CONTINUANCE OF PROCLAMATION IN RESPECT OF MANIPUR

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. C. PANT): I beg to move the following Resolution:

> "That this House approves the continuance in force of the Proclamation, dated 28th March, 1973, in respect of Manipur, issued under article 356 of the Constitution by the President, for a further period of six months with effect from the 14th November, 1973."

Members are fully aware of the circumstances in which the Proclamation dated the 28th March, 1973 was issued by the President. The justification for Parliamential Proclamation was also debated in this House on two earlier occasions. There is, therefore, no need to go into that question now. As the House is aware, the Legislative Assembly of Manipur has been dissolved and Popular rule can be restored only after new elections to the State Assembly are held. However, article 82 of the Constitution requires after each census the allocation of seats in the House of the People to the States and division of each State into territorial constituencies shall be readjusted. The Election Commission have accordingly taken up the delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies in all States including Manipur. We hope that this process will be completed in the course of the year and elections will be held early next year. But meanwhile there cannot be a vacucum. The period for which the House had earlier accorded its approval will expire on the 13th